



## राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)  
(A constitutional body exercising powers of a Civil Court under Article 338A of the Constitution of India)

### NOTICE

फा. सं.: NCST/DEV-1151/MP/19/2022-ESDW

दिनांक: 19.01.2023

सेवा में,

डॉ. पल्लवी जैन गोविल,  
प्रमुख सचिव,  
जनजातीय कार्य विभाग मध्य प्रदेश,  
आयुक्त कार्यालय, आदिवासी विकास,  
भोपाल -462004,  
मध्य प्रदेश  
ई-मेल: pstwd@mp.gov.in

विषय: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी जनजातियों पर किया जा रहा दुर्भावनापूर्ण व्यवहार एवं मानव अधिकारों के हनन को रोकने के संबंध में श्री नरेंद्र सिंह चौहान, ग्राम - देलवानी, पो. वालपुर, तहसील सोण्डवा, जिला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश का दिनांक 18.11.2022 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को श्री नरेंद्र सिंह चौहान से दिनांक 18.11.2022 में एक याचिका/शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है (प्रति संलग्न), और आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का अनुसरण करते हुए इस मामले का अन्वेषण/जांच करने का निश्चय किया है। अतः आपसे एतद्वारा अनुरोध किया जाता है कि आप सूचना के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को डाक से या वैयक्तिक रूप से उपस्थित होकर या किसी अन्य संचार साधन से संबन्धित आरोपों/मामलों और सूचनाओं पर की गई कार्रवाही से सम्बंधित सूचना प्रस्तुत करें।

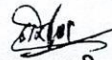
कृपया ध्यान रखें कि यदि नियत अवधि में आयोग में आपका उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत उसे प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है तथा वैयक्तिक रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपको 'समन' भी जारी कर सकता है।

संलग्न यथोपरि.

प्रतिलिपि संलग्न:

श्री नरेंद्र सिंह चौहान,  
ग्राम - देलवानी, पो. वालपुर,  
तहसील सोण्डवा,  
जिला अलीराजपुर,  
मध्य प्रदेश

70-71  
जारी किया  
15/01/23

  
(एच. आर. मीना)  
अनुसंधान अधिकारी